प्रयागराज में बाढ़ से घरों में भरा पानी, ओडिशा में 312 छात्र फँसे

हिमाचल में मानसून से 187 मौतें, कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित

नईदुनिया ब्यूरो, प्रयागराजः उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रयागराज की कई कॉलोनियों में तीन से चार फीट तक पानी भर गया है। कारें और बाइकें डूब गई हैं तथा कई घरों के भूतल में पानी भर गया है। लोगों को पहली मंजिल पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में 312 छात्र और 10 शिक्षक पिछले दो दिनों से स्कूल में फंसे हुए हैं। कुलसाही गांव स्थित सरकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय आश्रम विद्यालय का भूतल ब्राह्मणी नदी के पानी में डूब गया है। विद्यालय चारों ओर से करीब 10 फीट पानी से घिरा हुआ है। तेज बहाव के कारण अब तक बचाव दल वहां नहीं पहुंच सका है। केंद्रापाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 का करीब 100 मीटर हिस्सा भी धंस गया है। यह राजमार्ग पारादीप बंदरगाह को जाजपुर से जोड़ता है। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों में बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बुधबलंगा नदियों में जलस्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार को भारी बारिश हुई और सोमवार के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के घाट भी डूब गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं और सड़क हादसों से 187 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 जून से 16 अगस्त के बीच बाढ़, भूस्खलन, डूबने और करंट जैसी प्राकृतिक आपदाओं में 79 लोगों की मौत हुई, जबकि सड़क हादसों में 107 लोगों की जान गई। राज्य में 294 लोग घायल हुए हैं और 31 लोग अब भी लापता हैं। मानसून से राज्य में करीब 973 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। नई दिल्ली में भी वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है।

ट्रंप की प्रेस सचिव लेविट का इस्तीफा, कहा परिवार को देना चाहती हूं ज्यादा समय

ट्रंप ने मजाक में कहा- लेविट को मुझसे ज्यादा अपने बच्चे पसंद, बोले- उनकी जगह लेना आसान नहीं

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट अगस्त के अंत में अपने पद से इस्तीफा देंगी। उन्होंने अपने दो छोटे बच्चों और परिवार को अधिक समय देने के लिए यह फैसला लिया है। ट्रंप ने उनके निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि लेविट व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद भी उनकी टीम से जुड़ी रहेंगी और बाहरी सलाहकार के रूप में काम करेंगी।

लेविट के इस्तीफे पर ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि कैरोलिन लेविट उन्हें पसंद करने से ज्यादा अपने बच्चों को पसंद करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लेविट की जगह लेना आसान नहीं होगा। लेविट ने इसी सप्ताह पद छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने 1 मई 2026 को अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद वह मातृत्व अवकाश पर चली गई थीं और 16 जुलाई को प्रेस ब्रीफिंग में वापस लौटी थीं। 26 वर्षीय लेविट जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनी थीं और इस पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। उन्होंने कम्युनिकेशन और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान फॉक्स न्यूज में इंटर्नशिप की और ट्रंप के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस में काम किया। बाद में वह रिपब्लिकन सांसद एलिस स्टेफनिक की संचार निदेशक बनीं। 2024 में वह ट्रंप के चुनाव अभियान की प्रेस सचिव बनीं और जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव नियुक्त हुईं। उन्होंने 28 जनवरी 2025 को पहली प्रेस ब्रीफिंग की थी। लेविट के बाद अगली प्रेस सचिव कौन होगी, इसका अभी ऐलान नहीं हुआ है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्टर एलेक्सिस मैकएडम्स ने ट्रंप से इस बारे में सवाल किया। ट्रंप ने मजाक में उनसे पूछा कि क्या वह लेविट की जगह लेंगी और उनकी तारीफ भी की।

दीपके के दौरे के दो दिन बाद स्कूल में मरम्मत शुरू

टूटी खिड़कियां बदली जा रहीं, खराब सीसीटीवी कैमरों की जगह नए कैमरे; शौचालय में 24 घंटे पानी की व्यवस्था

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी गांव स्थित जिला परिषद स्कूल में मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। यह कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के स्कूल का निरीक्षण कर सुविधाओं की कमी का वीडियो जारी करने के दो दिन बाद शुरू हुई। दीपके 15 अगस्त को अपने गांव पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत की थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल की टूटी खिड़कियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूलों की अनदेखी से गरीब परिवारों के बच्चों को नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों की फीस पर सीमा लगाने की मांग की थी।

दीपके के दौरे के बाद स्थानीय ग्राम पंचायत ने स्कूल की मरम्मत का काम शुरू कराया। संतुक पिंपरी के सरपंच विजय पुरी ने बताया कि स्कूल में क्षतिग्रस्त खिड़कियां बदली जा रही हैं और उनके नए फ्रेम लगाए जा रहे हैं।

खराब सीसीटीवी कैमरों को भी बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल के शौचालय में पानी की समस्या थी, जिसे दूर करते हुए 24 घंटे पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े एक मामले में सीजेपी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के पिता मफीक की मौत हो गई। पार्टी के अनुसार, मफीक ने 13 अगस्त को करिसुंडा गांव के सरकारी स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया था। उसी शाम हथियारबंद लोगों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। गंभीर चोटों के बाद रविवार को उनकी मौत हो गई। सोमवार को सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने परिवार से मुलाकात की। परिवार ने आर्थिक मुआवजा लेने से इनकार करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और गांव के बच्चों के लिए उचित सरकारी स्कूल बनाने की मांग की। सीजेपी ने प्रशासन से अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, घटना की जांच, परिवार को सुरक्षा देने और मफीक के नाम पर सरकारी स्कूल बनाने की मांग की है।

शी जिनपिंग ने की तियानमेन की तारीफ

बीजिंग, एजेंसीः चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1989 के तियानमेन प्रदर्शन को रोकने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शी ने कहा कि उस समय जियांग ने पार्टी के फैसले का समर्थन किया और शंघाई में हालात को नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द, सीआईडी करेगी जांच

नईदुनिया ब्यूरो, रांचीः झारखंड सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि एसआईटी और सीआईडी की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है, इसलिए सभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि इसमें कई कंपनियों का आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क सामने आया है, जो अलग-अलग समय पर काम कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रमुख मांग जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी है। इसकी पूरी जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाएगी।

शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई

14 राज्यों में 253 लोग हिरासत में, पाकिस्तान निर्मित ग्रेनेड और आईईडी बरामद

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी नेटवर्क शहजाद भट्टी के खिलाफ 14 राज्यों में कार्रवाई की।

गृह मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त अभियान में नेटवर्क से जुड़े 253 लोगों को हिरासत में लिया गया और 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में बने ग्रेनेड, आईईडी, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

गृह मंत्रालय के अनुसार, 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ वास्तविक समय की खुफिया सूचना साझा करने की व्यवस्था के तहत यह संयुक्त अभियान चलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि शहजाद भट्टी नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था और स्वतंत्रता दिवस से पहले इसकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, नेटवर्क से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्ट्री की पहचान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद हुए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि आईएसआई से जुड़े इस नेटवर्क का संबंध ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों के साथ-साथ लक्षित हत्याओं से भी रहा है।

मंत्रालय के अनुसार, नेटवर्क स्थानीय मददगारों को पुलिस, रक्षा प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों की रेकी के लिए धन देता था।

अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने पर 28 लाख का इनामः हातमी

तेहरान, एजेंसीः ईरानी सेना ने किसी अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने वाले व्यक्ति को 30 हजार डॉलर यानी करीब 28 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है। सेना के कमांडर-इन-चीफ अमीर हातमी ने तेहरान में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यदि यह काम कोई महिला करती है तो इनाम की राशि बढ़ाकर 60 हजार डॉलर कर दी जाएगी।

हातमी ने कहा कि यह योजना कई मांगों के बाद बनाई गई है। इसका उद्देश्य उन लोगों को युद्ध प्रयासों में आर्थिक रूप से मदद करने का अवसर देना है, जो वित्तीय माध्यमों से सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष ने अमेरिका के सैन्य प्रभाव को कमजोर किया है और कई देशों को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़े हैं। हातमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करने संबंधी बयान की भी आलोचना की। ईरानी सेना की लापता लोगों की तलाश करने वाली समिति के प्रमुख जनरल सैयद मोहम्मद बाघेरजादेह ने रेड क्रॉस को पत्र लिखकर बताया कि तीनों पायलटों के विमान 2 मार्च को कतर की वायु रक्षा की चपेट में आए थे। पायलट पैराशूट से सुरक्षित उतरे, लेकिन बाद में कतर के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। ईरान ने पायलटों की स्थिति की जांच और उन्हें परिवार से मिलने देने की मांग की है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल-अंसारी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कतर ने किसी ईरानी पायलट को हिरासत में नहीं लिया है।

जरदारी के हिंदुओं को लेकर बयान पर भड़के जावेद अख्तर

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान में हिंदू आबादी को लेकर दिए बयान पर भारतीय संवाद लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जरदारी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति की तुलना भारत के हिंदुओं से करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में तीन से चार प्रतिशत हिंदू आबादी है और वे उन्हें सहन करते हैं। जरदारी ने कहा था कि भारतीयों का नजरिया अलग है और उनके दिमाग में अपना एजेंडा है। उन्होंने अखंड भारत में विश्वास का भी जिक्र किया। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी मुसलमान हैं, जबकि हिंदू नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू उतने ही स्वतंत्र और अच्छे हैं, जितने कहीं और थे। जावेद अख्तर ने सामाजिक माध्यम पर जरदारी की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जो बेनजीर भुट्टो से शादी करने के बाद सुर्खियों में आए थे, अपने देश की तीन से चार प्रतिशत हिंदू आबादी को बर्दाश्त करने की बात कहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जरदारी हमेशा उन चीजों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं, जिनका प्रतिशत 10 प्रतिशत से कम है।

जावेद अख्तर का यह तंज जरदारी के पुराने उपनाम 'मिस्टर टेन परसेंट' की ओर संकेत था।

याचिका *तमिलनाडु ने कर्नाटक से तय हिस्सा तुरंत छोड़ने की मांग की, अगली सुनवाई 24 अगस्त को...*

कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक सप्ताह टली

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कावेरी जल विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी। तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर कर कर्नाटक को राज्य के हिस्से का कावेरी जल तत्काल छोड़ने का निर्देश देने की मांग की है। अब मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने तीन अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद अदालत ने 12 अगस्त को तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई तय की थी। सोमवार को सुनवाई एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी गई।

तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कावेरी जल विनियमन समिति की ओर से राज्य के लिए निर्धारित पानी की मात्रा और कर्नाटक की ओर से छोड़ा जा रहा पानी, दोनों ही काफी कम हैं। 28 जुलाई को हुई समिति की बैठक में कर्नाटक को 29 जुलाई से 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

तमिलनाडु के अनुसार, 29 जुलाई से दो अगस्त के बीच बिलिगुंडुलु में पानी का प्रवाह केवल 158 से 550 क्यूसेक के बीच रहा। राज्य सरकार ने तीन अगस्त तक कर्नाटक के काबिनी, हरंगी और हेमावती बांधों में कुल 77.537 हजार मिलियन घन फीट पानी जमा होने का दावा किया। तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक के पास तय अनुपात के अनुसार पानी छोड़ने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध है।

कावेरी जल बंटवारे का विवाद करीब 142 वर्ष पुराना है। वर्ष 1881 में मैसूर रियासत ने कावेरी नदी पर बांध बनाने का निर्णय लिया था, जिसका तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी ने विरोध किया। इसके बाद 1892 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ।

वर्ष 1924 में कावेरी जल के निश्चित बंटवारे को लेकर 50 वर्ष के लिए समझौता हुआ। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए पानी का आवंटन तय किया गया था। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद समझौते में बदलाव की जरूरत पड़ी।

1960 के दशक में कर्नाटक ने नए जलाशय बनाने की योजना बनाई। केंद्र की आपत्ति के बावजूद चार जलाशयों का निर्माण किया गया। वर्ष 1974 में 1924 का समझौता समाप्त हो गया। इसके बाद कावेरी जल विवाद पर तथ्य खोज समिति बनाई गई, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 1976 में आई।

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी के अधिकार और आवश्यकता को लेकर विवाद जारी रहा। कर्नाटक का तर्क रहा है कि नदी के बहाव के रास्ते में वह पहले आता है, जबकि तमिलनाडु पुराने समझौतों और अपने हिस्से के पानी की जरूरत का हवाला देता रहा है।